03 मई 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

1. **भारतीय मसालों को चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ रहा हैं?**

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

राजव्यवस्था:

1. मानक आवश्यक पेटेंटों पर न्यायपालिका की छाया:

सामाजिक न्याय:

1. 'इस छुट्टी' को एक महिला के अधिकार के रूप में पहचानें:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. विदेशी पौधों को हटाने से जंगली जानवरों के लिए भोजन सुनिश्चित होगा: अध्ययन
2. NPCI की वैश्विक शाखा नामीबिया के लिए यूपीआई जैसी प्रणाली विकसित करेगी:
3. अप्रैल पीएमआई ने 42 महीनों में विनिर्माण क्षेत्र में दूसरी सबसे अच्छी बढ़त का संकेत दिया:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

भारतीय मसालों को चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ रहा हैं?

अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यात।

मुख्य परीक्षा: भारतीय मसालों के निर्यात में आने वाली चुनौतियाँ।

प्रसंग:

- अपने स्वाद और सुगंध के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय मसाले, विशेष रूप से एमडीएच और एवरेस्ट जैसे प्रमुख ब्रांडों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों में कथित संदूषण के मुद्दों के कारण यह मसाले जांच का सामना कर रहे हैं।

समस्याएँ:

- संदूषण के आरोप: हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों ने एमडीएच और एवरेस्ट उत्पादों में पाए जाने वाले खाद्य स्टेबलाइजर के रूप में इस्तेमाल होने वाले जहरीले रसायन एथिलीन ऑक्साइड के उच्च स्तर के कारण कुछ मसाला मिश्रणों की बिक्री को निलंबित कर दिया है या अस्थायी रूप से रोक लगा दी हैं।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: एथिलीन ऑक्साइड एक प्रतिबंधित कीटनाशक है, जो अधिक मात्रा में मौजूद होने पर जहरीले और कैंसरकारी यौगिकों के निर्माण का कारण बन सकता है। इन यौगिकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं।
- अस्वीकृतियों का इतिहास: साल्मोनेला संदूषण (salmonella contamination) और गलत ब्रांडिंग सहित विभिन्न मुद्दों के कारण नियामक निकायों, विशेष रूप से यू.एस. एफडीए द्वारा अस्वीकृति के पिछले उदाहरण, भारतीय मसाला निर्यात की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हैं।

महत्व:

- आर्थिक प्रभाव: भारतीय मसाला निर्यात पर इन जांचों और नियामक कार्रवाइयों के संभावित नतीजों के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, जिससे अरबों डॉलर का निर्यात दांव पर लग सकता है।

- उपभोक्ता सुरक्षा: मसाला उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और भारतीय मसाला निर्यात में उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

- किसानों की आजीविका: मसाला निर्यात में कोई भी गिरावट किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, विशेषकर छोटे पैमाने के किसानों पर, जो अपनी आजीविका के लिए मसाला व्यापार पर निर्भर हैं।

समाधान:

- नियामक उपाय: भारतीय मसाला बोर्ड ने निर्यातित उत्पादों का अनिवार्य परीक्षण शुरू कर दिया है और संदूषण के मुद्दों के समाधान के लिए निर्यातकों के साथ काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई (FSSAI) ने राज्य नियामकों को एथिलीन ऑक्साइड के लिए प्रमुख मसाला ब्रांडों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है।

- उन्नत खाद्य सुरक्षा मानक: खाद्य सुरक्षा मानकों को अद्यतन करने और वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित करने और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियामक निरीक्षण में सुधार करने का आह्वान किया गया हैं।

- बेहतर पता लगाने की क्षमता: संभावित जोखिमों की बेहतर निगरानी और नियंत्रण को सक्षम करने के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में पता लगाने की क्षमता को बढ़ाना।

Indian spices and herbs rejected by the U.S. FDA in 2023

A scrutiny of FDA's import refusal report, for the calendar year 2023, cites at least 30 instances wherein entry was refused because the products appeared to contain salmonella

Company	Products rejected	Reasons for rejection
Ramdev Food Products Pvt Ltd	Cumin	Appears to contain salmonella, a poisonous and deleterious substance which may render it injurious to health
	Mixed spices and seasoning	Salmonella
	Coriander	Salmonella
	Nutmeg	Salmonella
	Cumin	Salmonella
	Ginger	Salmonella
	Fennel	Artificial colouring, misbranding
Mahashian Di Hatti (MDH)	Paprika	Filthy, putrid, or decomposed substances otherwise unfit for food; and salmonella
	Mixed spices and seasoning	Salmonella
	Mixed spices and seasoning	Misbranding + salmonella
	Capsicums (cayenne chili, hot peppers) spice	Salmonella
	Spices and seasoning, ground, cracked with salt	Salmonella
Everest	Capsicums (cayenne chili, hot peppers) spice	Salmonella
	Spices and seasoning, ground, cracked with salt	Labelling violation of FPLA because of its placement, form and/or contents statement
	Black pepper	Salmonella
MTR Foods Private Limited	Curry powder, ground, cracked without salt	Salmonella
	Spices and seasoning, ground, cracked with salt	Salmonella
	Spices and seasoning, ground, cracked with salt	Labelling violation
Dharampal Satyapal Ltd. (DS Group Catch)	Mixed spices and seasoning	Appears to be misbranded in that the label or labeling fails to bear the required nutrition information; appears to contain a poisonous or deleterious substance which would ordinarily render the article injurious to health
Patanjali Ayurved Ltd.	Natural extract or flavour	Appears to be a new drug within the meaning of Section 201(p) without an approved New Drug Application (NDA)
Nestle India	Spices and seasoning, ground, cracked with salt	Salmonella
Badshah Masala Pvt. Ltd.	Spices and Seasoning, ground, cracked with salt	Labelling violation
Tulsi Foods	Black pepper	Filthy and salmonella
Speciality Indian Food Parks & Exports	Black pepper	Filthy and salmonella

U.S. FDA's Import Refusal Report

चित्र स्रोत: The hindu

सारांश:

- भारतीय मसाला निर्यात की वर्तमान जांच संदूषण के मुद्दों को संबोधित करने, खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और भारतीय मसाला उद्योग से जुड़ी प्रतिष्ठा और आजीविका की रक्षा के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। उपभोक्ता विश्वास बहाल करने और भारत के मसाला व्यापार की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नियामक अधिकारियों, उद्योग हितधारकों और वकालत समूहों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

मानक आवश्यक पेटेंटों पर न्यायपालिका की छाया:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

विषय: भारतीय न्यायपालिका।

मुख्य परीक्षा: मानक आवश्यक पेटेंट (standard essential patents (SEPs)) के प्रबंधन से संबंधित संकट।

प्रसंग:

- भारत विशेष रूप से दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) के प्रबंधन से संबंधित संभावित संकट का सामना कर रहा है।
- सेल्यूलर फोन के लिए भारत के घरेलू विनिर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण एसईपी की नियामक निगरानी को काफी हद तक न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ सुस्ती और सक्रियता दोनों सामने आई है।
    - एक मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) एक पेटेंट है,दूसरे शब्दों में मानक-आवश्यक पेटेंट एक पेटेंट है जो किसी मानक में उपयोग के लिए चयनित प्रौद्योगिकी की सुरक्षा करता

है।इसका उद्देश्य उद्योग मानक की रक्षा करना है। उदाहरणों में यूएसबी, वाई-फाई और जेपीईजी शामिल हैं।

समस्याएँ:

- एसईपी का महत्व: एसईपी उद्योग मानकों के रूप में अपनाई गई प्रौद्योगिकियों को कवर करता है, जो दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करता है।
- हालाँकि, इन मानकों को स्थापित करने में निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रभुत्व भारत जैसे देशों पर बहुत कम प्रभाव डालता है।
- पेटेंट होल्डअप समस्या: एसईपी के मालिक उच्च रॉयल्टी की मांग कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं और बाजार प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसे "पेटेंट होल्डअप" समस्या के रूप में जाना जाता है।
- न्यायिक प्रतिक्रिया: भारतीय न्यायपालिका द्वारा एसईपी से संबंधित मुद्दों को संभालने में देरी और सक्रियता की विशेषता रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन और पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे प्रभावित हुए हैं।

महत्व:

- घरेलू विनिर्माण पर प्रभाव: अनियमित एसईपी अनुचित लाइसेंसिंग शर्तों को लागू करके और प्रतिस्पर्धा में बाधा डालकर घरेलू विनिर्माण विकास को रोक सकता है, जिससे उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (production-linked incentives scheme) जैसी पहल के तहत निवेश को आकर्षित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों पर असर पड़ेगा।
- नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता: निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और घरेलू उद्योगों का समर्थन करने के लिए यूरोपीय संसद द्वारा लागू किए गए एसईपी-संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए नियामक उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय दायित्व: विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों के पेटेंट को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा मजबूर भारत को अपने घरेलू हितों की रक्षा करते हुए अपने दायित्वों के साथ नियामक हस्तक्षेप को संतुलित करना होगा।

समाधान:

- नियामक ढांचा: भारत सरकार को प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने और बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण लाइसेंसिंग शर्तों को सुनिश्चित करते हुए एसईपी को विनियमित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।
- न्यायिक सुधार: न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और एसईपी से संबंधित विवादों को हल करने में देरी को कम करने, समय पर न्याय सुनिश्चित करने और घरेलू विनिर्माण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- हितधारक परामर्श: सरकार को एक व्यापक नियामक ढांचा विकसित करने के लिए उद्योग हितधारकों, कानूनी विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ जुड़ना चाहिए जो भारत के हितों की रक्षा करते हुए एसईपी लाइसेंसिंग की जटिलताओं को संबोधित करता है।

सारांश:

- भारत में मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) को संभालना घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के लिए दूरगामी प्रभाव के साथ एक जटिल नीति चुनौती प्रस्तुत करता है। एसईपी से संबंधित विवादों को निपटाने में न्यायपालिका की भूमिका देरी और सक्रियता द्वारा चिह्नित की गई है, जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और भारत की विनिर्माण आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करती है। प्रभावी नियामक उपायों को लागू करने और हितधारक सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए एसईपी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकता है।

'इस छुट्टी' को एक महिला के अधिकार के रूप में पहचानें:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: भारत में मासिक धर्म अवकाश की चुनौतियाँ।

प्रसंग:

- भारत में मासिक धर्म की छुट्टी पर बहस ने गति पकड़ ली है, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाले कानून की वकालत करने का वादा किया है।
- हालाँकि, इस संबंध में विधायी प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो गहरी जड़ें जमा चुके लैंगिक पूर्वाग्रहों और संस्थागत बाधाओं को दर्शाता है।

विधायक और विधेयक:

- निजी सदस्य विधेयक: एस. जोथिमनी और निनॉन्ग एरिंग सहित कई संसद सदस्यों (सांसदों) ने मासिक धर्म अवकाश को एक महिला के अधिकार के रूप में स्थापित करने और इनकार करने पर जुर्माना लगाने की मांग करते हुए निजी सदस्य विधेयक (Private Member Bills) पेश किए हैं।
- प्रमुख प्रावधान: ये विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सवैतनिक अवकाश, मासिक धर्म के दौरान आराम की अवधि और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं तक पहुंच जैसे अधिकारों का प्रस्ताव करते हैं।
- न्यायिक प्रतिक्रिया: विधायी प्रयासों के बावजूद, मासिक धर्म अवकाश पर न्यायपालिका का रुख निष्क्रिय रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के नीति क्षेत्र को टाल दिया है, जिससे नियामक स्पष्टता की कमी हो गई है।

प्रगतिशील भारतीय राज्य, एशियाई राष्ट्र:

- राज्यों की पहल: केरल और बिहार जैसे राज्य ऐतिहासिक रूप से मासिक धर्म अवकाश को मान्यता देने में अग्रणी रहे हैं, जबकि केरल ने हाल ही में इसे 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, अन्य राज्यों को ऐसे उपायों को सक्रिय रूप से लागू करने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मिसालें: जापान, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया सहित कई एशियाई देशों ने मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून बनाया है, जो इस मुद्दे को संबोधित करने में भारत की देरी को उजागर करता है।
- वैश्विक वकालत: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization (WHO)) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में इसके महत्व पर जोर देते हुए महिलाओं के अधिकार के रूप में मासिक धर्म अवकाश का समर्थन किया है।

अधिक लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता:

- श्रम कानून: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे प्रमुख कानून में मासिक धर्म की छुट्टी की अनुपस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- नीति समाधान: लैंगिक असमानताओं के सामाजिक-सांस्कृतिक और जैविक आयामों को संबोधित करने, वर्जनाओं को चुनौती देने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए लिंग-संवेदनशील नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
- राजनीतिक प्रतिबद्धता: राजनीतिक दलों द्वारा मासिक धर्म अवकाश को मान्यता देना महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को संबोधित करने में एक प्रगतिशील बदलाव का संकेत है।

सारांश:

- भारत में मासिक धर्म की छुट्टी को लेकर बहस लैंगिक भेदभाव और संस्थागत पूर्वाग्रहों के

व्यापक मुद्दों को दर्शाती है। हालाँकि विभिन्न स्तरों पर विधायी प्रयास शुरू किए गए हैं, लेकिन मासिक धर्म अवकाश को महिलाओं के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए सक्रिय उपायों की तत्काल आवश्यकता है। नीतिगत सुधारों की वकालत करके, लिंग-संवेदनशील हस्तक्षेपों को बढ़ावा देकर और राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देकर, भारत लैंगिक समानता हासिल करने और कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. विदेशी पौधों को हटाने से जंगली जानवरों के लिए भोजन सुनिश्चित होगा: अध्ययन

प्रसंग:

- केरल राज्य वन सुरक्षा कर्मचारी संगठन द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में जंगली जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से चिन्नक्कनाल, मुन्नार में वन क्षेत्रों से विदेशी पौधों को हटाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
- एक अध्ययन द्वारा इस क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

समस्याएँ:

- विदेशी पौधों का आक्रमण: चिन्नक्कनाल, मुन्नार के वन क्षेत्रों में बबूल मर्नसी और नीलगिरी जैसी विदेशी पौधों की प्रजातियों का प्रभुत्व है, जो देशी वनस्पति के विकास को रोकते हैं और हाथियों सहित जंगली जानवरों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हैं।
- वन्य जीवन पर प्रभाव: विदेशी पौधों की उपस्थिति जंगली जानवरों को प्राकृतिक भोजन स्रोतों से वंचित करती है और उनके आवास को बाधित करती है, जिससे मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष होता है।

- प्रतिबंधित हाथियों की आवाजाही: भूदृश्य/परिदृश्य, विशेष रूप से चिन्नक्कनाल में, जो पश्चिम भारतीय लैंटाना से भारी रूप से प्रभावित है,जिससे हाथियों की आवाजाही सीमित हो गई है और मानव-पशु संघर्ष (human-animal conflicts) बढ़ गया है।

महत्व:

- वन्यजीव संरक्षण: विदेशी पौधों को हटाने और प्राकृतिक घास के मैदानों को बहाल करने से आवास की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और जंगली हाथियों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी के स्रोत सुनिश्चित होंगे, जो वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में योगदान देंगे।
- मानव-हाथी संघर्ष शमन: विदेशी पौधों के आक्रमण के मुद्दे को संबोधित करना और हाथी गलियारों को फिर से खोलना, जैसा कि विशेषज्ञ पैनलों द्वारा अनुशंसित है, मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- पर्यावरण बहाली: वन क्षेत्रों में देशी वनस्पति को बहाल करने से न केवल वन्यजीवों को लाभ होगा बल्कि समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और लचीलेपन में भी सुधार होगा।

समाधान:

- विदेशी पौधे हटाना: चिन्नक्कनाल, मुन्नार के वन क्षेत्रों से बबूल मर्नसी, नीलगिरी और वेस्ट इंडियन लैंटाना जैसे आक्रामक विदेशी पौधों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- गलियारा फिर से खोलना: हाथी गलियारों को फिर से खोलने की सिफारिश को लागू करने से, जैसे कि मुन्नार में अनायिरंकल से पुराने देवीकुलम तक का मार्ग, हाथियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा और मानव बस्तियों के साथ संघर्ष को कम करेगा।

2. NPCI की वैश्विक शाखा नामीबिया के लिए यूपीआई जैसी प्रणाली विकसित करेगी:

प्रसंग:

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India (NPCI)) की वैश्विक सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के समान तत्काल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के विकास में सहायता के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया है।
- इस सहयोग का उद्देश्य नामीबिया के वित्तीय बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए यूपीआई के साथ भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाना है।

समस्याएँ:

- नामीबिया में वित्तीय अवसंरचना: नामीबिया में भारत के यूपीआई के समान मजबूत तत्काल भुगतान प्रणाली का अभाव है, जो देश में वित्तीय लेनदेन की दक्षता और पहुंच को बाधित करता है।
- आधुनिकीकरण की आवश्यकता: एनआईपीएल और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच साझेदारी दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- तकनीकी स्थानांतरण: भारत की यूपीआई तकनीक और विशेषज्ञता को नामीबिया में स्थानांतरित करना नामीबिया की विशिष्ट आवश्यकताओं और नियामक ढांचे के अनुरूप प्रणाली को अपनाने जैसी चुनौतियां पेश करता है।

महत्व:

- उन्नत वित्तीय समावेशन: नामीबिया में यूपीआई (UPI) के समान तत्काल भुगतान प्रणाली के विकास में व्यापक आबादी को सुविधाजनक और सुलभ डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की क्षमता है।
- दक्षता और नवाचार: आधुनिक भुगतान प्रणालियों को अपनाने से वित्तीय लेनदेन में दक्षता को बढ़ावा मिलता है, फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: एनआईपीएल और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच साझेदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझा करने के महत्व का उदाहरण देती है।

3. अप्रैल पीएमआई ने 42 महीनों में विनिर्माण क्षेत्र में दूसरी सबसे अच्छी बढ़त का संकेत दिया:

प्रसंग:

- एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के अनुसार, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अप्रैल में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जिसमे साढ़े तीन साल में दूसरा सबसे अच्छा लाभ दर्ज किया गया हैं।
- पिछले महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ी राहत के बावजूद, नए ऑर्डर और आउटपुट वृद्धि जैसे प्रमुख संकेतक मजबूत बने रहे, जो इस क्षेत्र में निरंतर गति का संकेत दे रहे हैं।

समस्याएँ:

- विनिर्माण गतिविधि में थोड़ी नरमी: एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई (Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI)) मार्च के 16 साल के उच्चतम 59.1 से गिरकर अप्रैल में 58.8 पर आ गया, जो विनिर्माण गतिविधि में मामूली मंदी का संकेत देता है।
- मांग में विचलन: जबकि नए ऑर्डर लगभग 40 महीनों में दूसरी सबसे तेज गति से बढ़े, घरेलू मांग ने निर्यात ऑर्डर को पीछे छोड़ दिया, जो घरेलू बाजार की मजबूती को दर्शाता है।
- लागत दबाव: एल्युमीनियम, कागज, प्लास्टिक और स्टील जैसी सामग्रियों की ऊंची कीमतों के साथ-साथ श्रम लागत में वृद्धि के कारण इनपुट लागत में वृद्धि हुई, जिससे निर्माताओं के लिए चुनौतियां खड़ी हो गईं।

महत्व:

- थोड़ी राहत के बावजूद, पीएमआई डेटा से पता चलता है कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र मजबूत विकास गति बनाए रखता है, जो निर्माताओं के बीच मजबूत मांग और विश्वास के स्तर से समर्थित है।
- रोजगार के अवसर: निर्माताओं ने मध्यम गति से नियुक्तियां बढ़ाईं, जो संभावित रोजगार के अवसरों और समग्र आर्थिक सुधार और आजीविका में योगदान का संकेत है।
- चुनौतियों के बीच लचीलापन: लागत दबाव के बावजूद, निर्माता भविष्य की मांग की स्थिति के बारे में आशावादी बने हुए हैं, जिससे इन्वेंट्री-निर्माण पहल और उच्च आउटपुट शुल्क को बढ़ावा मिलेगा, जो बेहतर मार्जिन का समर्थन कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. UPI एक डिजिटल और वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित और विनियमित किया जाता है।
2. इसे एकल दो-क्लिक कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से पीयर-टू-पीयर अंतर-बैंक हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. विभिन्न बैंक खातों तक पहुंचने के लिए यूपीआई को केवल एक ही मोबाइल ऐप की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

- यूपीआई एक डिजिटल और वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित है।

प्रश्न 2. क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक सर्वेक्षण-आधारित आर्थिक संकेतक है जो विभिन्न व्यवसायों में क्रय प्रबंधकों की धारणा का मूल्यांकन करता है।
2. इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक बनाया जाता है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 3. स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट के संबंध में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह एक मानक के कार्यान्वयन और कामकाज के लिए आवश्यक तकनीकी आविष्कारों के लिए दिया गया पेटेंट है।
2. ये एक मानक के लिए आवश्यक हैं और इन्हें एक मानक सेटिंग संगठन (एसएसओ) द्वारा अपनाया गया है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 4. विदेशी प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विदेशी प्रजातियों को उस क्षेत्र की मूल प्राकृतिक प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है जहां उन्हें लाया जाता है।
2. विदेशी प्रजातियों के विपरीत, आक्रामक प्रजातियाँ हमेशा उस पर्यावरण के लिए चिंता का कारण होती हैं जिसमें उन्हें लाया जाता है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

- सभी कथन सही हैं।

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केरल ने सबसे पहले छात्रों के लिए "पीरियड लीव" की आवश्यकता को पहचाना और 1912 में परीक्षाओं के दौरान इसकी अनुमति दी।
2. बिहार ने 1992 में सरकारी कर्मचारियों को दो दिन की मासिक छुट्टी की अनुमति दी।
3. सामाजिक सुरक्षा पर भारत के नए कोड, 2020 ने अपने कोड में मासिक धर्म अवकाश के पहलू को

शामिल किया है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

- संसद द्वारा पारित सामाजिक सुरक्षा पर भारत का नया कोड, 2020, जिसने मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित किया है, ने अपने कोड में मासिक धर्म अवकाश के पहलू को शामिल नहीं किया है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक मानकों से मेल खाने के लिए भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संबंध में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जीएस III - (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - II, राजव्यवस्था) (India still has a long way to go in order to match up to the global standards of Intellectual Property Rights. Do you agree? Highlight the role of the judiciary in this regard. (15 marks, 250 words) [GS-2, Polity/GS-3, IP]**)**

प्रश्न 2. हमारा निर्यात दुनिया भर में हमारा ध्वजवाहक है और गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय मसालों के संबंध में हाल के विवादों के आलोक में चर्चा कीजिए। जीएस III - (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - III, अर्थव्यवस्था) (Our exports are our flagbearers around the world and shouldn't be compromised on quality. Discuss in light of the recent controversies regarding Indian spices. (15 marks, 250 words) [GS-3, Economy]**)**

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU'S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)